दिल्ली विद्युत बोर्ड में वितरण और पारगम्यता हानि

835 **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जरवरी, 1998 के दैनिक "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित "हाफ हाफ डी.वी. बीज पावर वेनिशेज इन टु थिन लेयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वितरण एवं पारगम्यता हानि जो 1992-93 में 23% आंकी गई थी, वह 1996-97 में बढ़कर 50% हो गई है; और

(ग) यदि नहीं तो उपरोक्त दोनों वर्षों में दिल्ली राज्य में कितनी-कितनी बिजली उपलब्ध थी, तथा उक्त अवधि हेतु उपभोग की गई बिजली के लिए वर्ष-वार कितनी राशि के बिल तैयार किए गए?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि पारेक्षण और वितरण हानि वर्ष 1992-93 के 23.98% में बढ़कर वर्ष 1996-97 में 49.85% हो गई है। इन्हीं वर्षों के दौरान विद्युत की उपलब्धता 10,517 मिलियन यूनिट से बढ़कर 13,703 मिलियन यूनिट हो गई है और बिल की राशि 1072 करोड़ रूपये से बढ़कर 1782 करोड़ रूपये हो गई है।

बांध के निर्माण के कारण गंगा में प्रदूषण

836. **श्री मनोहरकान्त ध्यानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टिहरी में भागीरथी (गंगा) नदी पर बनने वाले हजारों करोड़ के बांध के निर्माण को लेकर विभिन्न कोणों से विरोध होता रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व हिन्दू परिषद् ने इस जलाशय के निर्माण से गंगा की पवित्रता नष्ट होने की आशंका व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी शंका के समाधान के क्या उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पानी की गुणवत्ता के संबंध में रूड़की विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन कार्य किया गया था। अध्ययन कार्य से पता लगा था कि पानी रोकने के कारण पानी की गुणवत्त पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमंताराव समिति जो परियोजना के पर्यावरणीय और पारस्थिति की पहलुओं का जांच कार्य कर रही है ने यह सिफारिश की थी कि जलाशय के डाउन स्ट्रीम पर पानी की गुणवत्ता पर सम्भावित संघानं की जांच के संबंध में अध्ययन कार्य किए जाने चाहिए। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि॰ को जल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन स्थापित करने की सलाह प्रदान की गई है ताकि जलाशय में पानी के गुणवत्ता की मानीटरिंग की जा सके। टीएचडीसी को डाउन स्ट्रीम जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले सम्भावित संघातं का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन कार्य करने की सलाह दी गई हैं यह उल्लेख किया जा सकता है कि जलाशय में पानी की कमी होने के कारण वर्षा की कमी तथा मानसून के जल का लगातार प्रवाह हो सकेगा। वर्षा की कमी के दौरान पानी छोड़े जाने से नदी में दौरान जल प्रवाह की स्थिति में सुधार आयेगा।

टिहरी बांध का निर्माण पूरा होना

837. **श्री मनोहरकान्त ध्यानी:** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध पर अब तक ऐसे बांधों की तुलना में कई गुना अधिक राशि लगने के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य कई वर्ष पीछे चल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में आने वाले टिहरी नगर एवं आस-पास के पूर्णतया डूब जाने तथा आंशिक रूप से डूब जाने की आशंका वाले क्षेत्र में आने वाले ग्रामों का पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक सभी लोगों का पुनर्वास किए जाने का विचार है तथा इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है; और

(घ) क्या यह सच है कि यहां के मूल निवासियों के अलावा बहुत से अनधिकृत व्यक्तियों को नई टिहरी में प्लाट आबंटित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना को मूलत: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के तौर पर निष्पादित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की लागत 1370.86 करोड़ रूपये (1987 के मूल्य स्तर पर) थी। वर्ष 1989 में इसके राज्य सरकार से टिहरी जल विद्युत विकास निगम को अंतरित किए जाने के पश्चात् 1000 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता के साथ जल विद्युत परियोजना चरण-I और टिहरी बांध का अनुमोदन 2815 करोड़ रूपये (मार्च, 1993 के मूल्य स्तर पर) की

अनुमानित लागत पर किया गया था। इस परियोजना की अनंतिम संशोधित लागत दिसम्बर, 1997 के मूल्य स्तर पर 4570 करोड़ रूपये है। लागत में वृद्धि, समान्य मूल्य बढ़ोतरी, पुनर्वास पैकेज पर व्यय और पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों के कारण से है। उत्तराखंड आंदोलन से परियोजना का निर्माण कार्य पिछड़ गया और पर्यावरण आंदोलनकारियों द्वारा आमरण अनशन करने से कार्य में बार-बार रूकावट उत्पन्न हुई। अब परियोजना संतोषजनक रूप से चल रही है। इस परियोजना को अब वर्ष 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) परियोजना से प्रभावित जनता का पुनर्वास टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-I में काफर बांध के निर्माण से प्रभावित गांव की जनता और न्यू टिहरी टाउन का निर्माण शामिल है। चरण-I ग्राम पुनर्वास 98.5% जनता को प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने और भूमि का आबंटन किए जाने के साथ लगभग पूरा हो चुका है। देहरादून-ऋषिकेश में पुनर्वास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। शहरी जनता के पुनर्वास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। शहरी जनता के पुनर्वास हेतु निर्मित आवासीय प्लाटों के 98% आवासीय फ्लैटों के 70% और दुकानों के 75% आबंटन किया जा चुका है। चरण-2 में मुख्य बांध के निर्माण द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित बचे हुए ग्रामीण परिवार और आंशिक रूप से प्रभावित परिवार शामिल है। चरण-2 पुनर्वास के अंतर्गत 15% से अधिक ग्रामीण विस्थापित परिवारों को उनकी इच्छा के अनुसार पुन:स्थापित कर दिया गया है। शेष ग्रामीण परिवारों के लिए उन्हें स्थापित करने हेतु टीएचडीसी द्वारा अतिरिक्त कृषि भूमि को अधिगृहीत करने हेतु कदम उठाए गए हैं। सभी परिवारों को जलाशय की खुदाई से पूर्व पूरी तरह से पुन: स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार सक्रियता से पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल है जिसमें भूमि का अधिग्रहण तथा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान करना शामिल है।

(घ) टिहरी नगर में रहने वाले सभी हकदार परिवारों को नये टिहरी नगर में भू-खंडों का आबंटन कर दिया गया है। आबंटन समिति द्वारा कुछ व्यवसायिकों जैसे डॉक्टरों को भी कुछ भू-खंडों का आबंटन किया गया है ताकि सामाजिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

Involvement of Private Sector in DVB

838.*SHRI GHUFRAM AZAM:* Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Delhi Vidyut Board propose to involve private sector for some of its task:

(b) if so, whether the approval of Government have been taken for indulging private sector;

(c) if so, the details of the firms to which the DVB propose to assign the task; and

(d) to what extent the power related problems would be solved?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes Sir, As reported by DVB it proposes to involve private sector for power generation as well as distribution of electricity.

(b) The involvement of private sector by DVB for its power generation and distribution proposals is in line with Government of India policy.

(c) As regards proposed involvement of private sector by DVB in power generation project, the details as given by DVB are as under:

S.No.	Name of the Project	Name of the Firms which DVB popose to assign the task/involve.
I.	GENERATION	
1.	Combined Cycle Gas based Project Bawana Ph-I-421MW	M/s. Reliance Industries Ltd.
2.	Bawana Ph-II (600-650 MW)	Developer will be selected after opening of price bids.
3.	Replacement of Indraprastha Power Station-900 MW	Feasitility study is in progress by the Consultants of DVB, namely the NTPC.
4.	Captive Power Plants	A number of enterpreneurs in Delhi have shown their interest.